अशोका एक्सप्रेस

SMA - Ashoka Express Publication

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती

प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्ष: 29 ● अंक : 18 ● नई दिल्ली ● 16 से 22 मई 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

उन्नाव कांड - कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, 2 महीने में मुख्य याचिका पर फैसले का निर्देश

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस हमलावर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया महंगाई मैन

नई दिल्ली ।

कांग्रेस पार्टी ने देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपये की बढ़ोतरी करके जनता पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में इस वृद्धि को चार रायों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने से जोड़ते हुए कहा कि चुनाव के बाद पीएम मोदी की वसूली शुरू हो गई है।

महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया- कांग्रेस

कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज एक बार फिर जनता पर करारा प्रहार किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपये की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, सीएनजी की कीमतों में भी दो रुपये की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू।

पीएम मोदी पर कांग्रेस का करारा हमला

इसी के साथ कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक अलग पोस्ट में लिखा- अमेरिका में अदाणी पर चल रहा फ्रॉड का केस बंद हो जाएगा, अब साफ है कि मोदी ने अमेरिका के साथ एकतरफा डील इसलिए की ताकि अदाणी को राहत मिल सके। यही वजह है कि मोदी अमेरिका के आगे खुलकर बोल नहीं पाते हैं, ट्रंप जितना कहते हैं, मोदी उतना ही करते हैं। मोदी पूरी तरह से कॉमप्रोमाइड हैं।

भारत से संबंध बेहद अहम- अराघची

नई दिल्ली । ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत और ईरान के बीच मजबूत रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में बातचीत के दौरान उन्होंने भारत सरकार की मेहमाननवाजी की सराहना करते हुए कहा कि भारत के साथ संबंध ईरान के लिए बेहद अहम हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को अपना अच्छा मित्र बताते हुए दोनों देशों के बीच मजबूत संवाद का भी जिक्र किया। अब्बास अराघची ने कहा कि भारत सरकार और भारतीय प्रतिनिधियों ने उनके और उनके डेलिगेशन का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने खास तौर पर एस. जयशंकर के साथ अपने व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को मजबूत बताया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले दो महीनों के दौरान दोनों नेताओं के बीच लगातार संपर्क बना रहा, खासकर उस समय जब उनके देश में संघर्ष की स्थिति थी। उन्होंने कहा कि जिस संघर्ष को दुनिया युद्ध कह रही है, उसे वह अपने देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई मानते हैं। इस दौरान भारत और ईरान के बीच लगातार बातचीत होती रही। भारत और ईरान के संबंध लंबे समय से ऐतिहासिक और आर्थिक साझेदारी पर आधारित रहे हैं। ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लगातार सहयोग देखने को मिलता रहा है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है, ईरानी विदेश मंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब्बास अराघची ने अपने बयान में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जयशंकर के साथ उनकी व्यक्तिगत और कार्य संबंधी समझ काफी अच्छी है। दोनों नेता लगातार संपर्क में रहे हैं और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करते रहे हैं।

ट्रम्प की चीन यात्रा का अर्थ

इसमें कोई दो राज्य नहीं हो सकती कि वर्तमान में विश्व राजनीति में जो हड़कम्प मचा हुआ है उसके लिए पूरी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को पुनः महान बनाने के चक्कर में पूरे विश्व क्रम को झिंझोड़ कर रख दिया है और यूरोप समेत समस्त एशिया व अफ्रीकी देशों के समक्ष आत्म सम्मान बचाने का संकट पैदा कर दिया है। भारत के पड़ोस ईरान में जो अमेरिका व इजराइल मिल कर ईरान के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं उससे विश्व के अधिसंख्य देशों के समक्ष ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति शेखी बघार रहे हैं कि अमेरिका के पास पैट्रोलियम तेल व गैस की कमी नहीं है। दरअसल यह अमेरिका की वह हठधर्मिता है जिसकी वजह से दुनिया के विकासशील एशियाई व अफ्रीकी देशों को अपने विकास के लिए कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। ऐसे विश्व वातावरण में ट्रम्प चीन की यात्रा पर हैं जहां वह इस देश के साथ अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में ट्रम्प चीन की यात्रा पर अपने राष्ट्रीय हित इस प्रकार साधने गये हैं कि चीन जैसा तेजी से विकास करता देश अमेरिका की सहायता के बिना कुछ न कर सके। मगर चीनी नेता भी बहुत तेज हैं और वे एशिया व अफ्रीका में अपने बढ़ते निवेश पर अमेरिकी नजर नहीं पड़ने देना चाहते। मगर यह भी सत्य है कि अमेरिका व चीन के बीच विश्वास की भारी कमी पैदा हो चुकी है जिसकी वजह से ट्रम्प कभी चीन पर भारी शुल्क दरें लगाने का ऐलान करते हैं तो कभी उसके साथ मतभेदों को दूर करने की तजवीजें ढूंढते हैं। चीन ने पिछले 15 वर्षों के दौरान आर्थिक मोर्चे पर जो बढ़त प्राप्त की है उसकी वजह से अमेरिका व चीन की अर्थ व्यवस्थाएं एक-दूसरे पर निर्भर होती जा रही हैं। एक तरफ चीन जहां दुनिया का उत्पादन केन्द्र बन चुका है और सामान्य उपभोक्ता सामग्री से लेकर टैक्नोलॉजी उत्पादन क्षेत्र तक में उसका दबदबा कायम हो चुका है वहीं अमेरिका उच्च टैक्नोलॉजी के क्षेत्र शोध व उन्नयन पर अपना कब्जा जमाये हुए हैं। अमेरिका की वरीयता है कि उसके बोइंग वायुयान से लेकर बीफ (मांस) सोयाबीन और बोर्ड ऑफ ट्रेड को संरक्षण मिले। बोर्ड ऑफ ट्रेड के माध्यम से अमेरिका सेमी कंडक्टर व क्रत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर चीन को पछाड़े। अमेरिका चाहता है कि ऐसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाकर वह चीन के साथ अपने कारोबार में सन्तुलन लाये। क्योंकि चीन अमेरिका को जितना निर्यात करता है अमेरिका उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। दूसरी तरफ चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान के मामले में अपनी जिद छोड़े और उसे किसी प्रकार की मदद न दे। जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है तो चीन की कोशिश है कि अमेरिका उसके साथ उच्च टैक्नोलॉजी साझा करे और उसके आयात पर शुल्क की मुनासिब दर ही लागू करे। मगर इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू ईरान में चल रही लड़ाई भी है।

ईरान के पक्ष में रूस व चीन इस प्रकार हैं कि वे हर कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान का समर्थन करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का कोई भी वार निरुद्देश्य करते रहते हैं। हालांकि चीन प्रत्यक्ष रूप से ईरान की सैनिक मदद नहीं कर रहा है मगर उससे तेल की खरीदारी जारी रख कर वह उसकी अर्थ व्यवस्था को ढहने से बचाने का प्रयास भी कर रहा है। चीन अमेरिका को दुर्लभ खनिज पदार्थों की सप्लाई करने में भी कंजूसी बरत रहा है जबकि इन पदार्थों का दुनिया में वह सबसे बड़ा वितरक है। इससे अमेरिका के वाणिज्यिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है। अतः चीन व अमेरिका इस समय एकदूसरे के साथ 'तू डाल-डाल मैं पात-पात' की तर्ज पर चल रहे हैं और सन्देश दे रहे हैं कि किसी एक की शर्त पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। इसका विश्व व्यवस्था के क्रम पर उल्टा असर पड़ रहा है क्योंकि पहले से बनी व्यवस्था के तहत बने नियामक इस प्रकार टूट रहे हैं कि कथित विकसित यूरोपीय देश व विकासशील एशियाई देश एक ही पंक्ति में खड़े नजर आने लगते हैं। यह संस्थागत तरीके से विश्व क्रम को उलटने का फार्मूला है जो ट्रम्प का इजाद किया हुआ है। अतः ट्रम्प व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भेंट के बाद इस बात की संभावना ज्यादा है कि यदि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में और प्रगाढ़ता न भी आये तो स्थिरता जरूर आये। यह स्थिरता विश्व क्रम की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी मानी जा रही है जिसके परिक्षेत्र में ईरान में चल रहा युद्ध भी आता है । चीन कूटनीतिक रूप से अमेरिका पर दबाव बना सकता है कि वह ईरान में स्थायी युद्ध विराम की घोषणा करे वरना चीन भी अमेरिका की भांति ताइवान को दी जा रही सैनिक मदद की तरह ईरान के पाले में खड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति भारत समेत विभिन्न अन्य देशों के लिए किसी भी तरह से प्रिय नहीं होगी क्योंकि तब युद्ध की विभीषिका नये तेवरों में प्रकट हो सकती है। अतः बहुत जरूरी है कि इन दोनों विश्व शक्तियों के बीच स्थिरता का वातावरण बने जिससे विश्व में बेचैनी और न बढ़े। मगर ट्रम्प के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नवम्बर महीने में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं और इस दौरान ट्रम्प की अपने देश में लोकप्रियता काफी घट गई है। अतः उनके लिए जरूरी है कि वह चीन से खाली हाथ न लौटें।

सम्पादकीय

मजबूत आधारशिला

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उ0प्र0 डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज हर कार्य कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन किये जा रहे है। आज के डिजिटल युग में सरकारी विभागों की बढ़ती ऑनलाइन सेवाओं, विशाल डाटा के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन्स के केंद्रीकृत संचालन तथा नागरिकों तक त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं पहुंचाने की चुनौती लंबे समय से सामने रही है। अलग-अलग सर्वरों एवं बिखरी हुई तकनीकी व्यवस्थाओं के कारण डाटा सुरक्षा, सेवा निरंतरता एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना कठिन हो रहा था। इसी चुनौती के समाधान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अंतर्गत उ.प्र. स्टेट डाटा सेन्टर (यूपीएसडीसी) की स्थापना की गई, जो आज राय की ई-गवर्नेन्स व्यवस्था का एक सशक्त और विश्वसनीय आधार बन गया है। यूपीएसडीसी के माध्यम से राय के विभिन्न विभागों की जी-टू-सी तथा जी-टू-जी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। इसके तहत विभागों के डाटा एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को केंद्रीकृत रूप से सुरक्षित रखा जाता है, जिससे नागरिकों तक सेवाओं की त्वरित एवं पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश सरकार की नीति के तहत वर्तमान में लगभग 65 विभागों की 265 से अधिक विभिन्न एप्लीकेशन्स एवं वेबसाइट्स यूपीएसडीसी पर होस्टेड हैं। यह प्लेटफॉर्म विभागों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर विस्तार प्राप्त कर रहा है तथा विभिन्न विभागों को उनकी वेबसाइट एवं एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए आवश्यक स्पेस उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण ई-ऑफिस योजना भी यूपीएसडीसी पर सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, जिसके माध्यम से शासकीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और गति आई है। ई-ऑफिस प्रणाली ने सरकारी कार्यालयों में फाइलों के डिजिटल निस्तारण को बढ़ावा देते हुए पेपरलेस प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। डाटा सेन्टर की क्षमता वृद्धि एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके विस्तारीकरण का कार्य भी किए गए हैं। विस्तारीकरण के अंतर्गत नॉन-आईटी उपकरणों की स्थापना में 36 नवीन रैक्स लगाए गए हैं, जिनकी विद्युत भार क्षमता 14 किलोवाट से 21 किलोवाट तक है। इसके अतिरिक्त 2200 केवीए के 02 ट्रांसफार्मर, 1250 केवीए के 03 जेनसेट, 400 केवीए के 06 यूपीएस, एच.टी./एल.टी. पैनल सहित अन्य सहवर्ती उपकरणों की स्थापना कर यूपीएसडीसी को और अधिक सक्षम एवं सुरक्षित बनाया गया है।

देश की गोल्डन स्ट्रेटेजी

भारत में सोना केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव की चीज है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहराते वैश्विक आर्थिक संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीयों से कम से कम एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। सोना खरीदने का सीधा संबंध हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से होता है। भारत को सोने के हर एक औंस का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। सोने की जितनी ज़्यादा खरीद उतनी डॉलर की मांग भी बढ़ती है और जितनी मांग बढ़ती है, उतनी डॉलर की कीमत भी बढ़ जाती है। भारत सरकार ने भी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दो दशकों में भारत ने लगातार अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ाई है। दूसरी तरफ भारतीय परिवारों के लिए सोना न केवल पारंपरिक गहनों के रूप में एक फैशन है, बल्कि यह समृद्धि, सुरक्षा और मुद्रास्फीति के खिलाफ एक दीर्घकालिक रक्षा के रूप में भी कार्य करता है। अनुमान के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू 5 ट्रिलियन डॉलर (450 लाख करोड़) के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश की कुल 4.1 ट्रिलियन डॉलर यानी, 370 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। 'यह आंकड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में सोने के सांस्कृतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक महत्व को दर्शाता है।'आमतौर पर माना जाता है कि जब किसी संपत्ति की कीमत बढ़ती है तो लोग खुद को अमीर महसूस करते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। इसे वैल्थ इफेक्ट यानी धन का प्रभाव कहते हैं। भारत में 75-80 प्रतिशत सोना ज्वेलरी के रूप में है। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह देखते हैं। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच सोना फिर से मजबूत और सुरक्षित निवेश के रूप में उभर रहा है। भारत में इस रणनीति को संभालने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जिसने हाल के वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर दुनियाभर में देखने को मिल रहा है। इसी वजह

से भारत की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। तनाव की स्थिति इस कदर बिगड़ रही है कि अब भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तेज हो गया है। इसके लिए विदेशों में रखा भारत का सोना वापस लाया जा रहा है। वहीं आरबीआई की अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 की रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास इस वक्त कुल 880.52 मीट्रिक टन सोना है। इसका लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा यानी करीब 680 टन अब देश में ही सुरक्षित रखा गया है। सिर्फ 6 महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 104.23 मीट्रिक टन सोना अपने भंडार में जोड़ा। वहीं 197.67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास है, जबकि 2.8 टन जमा के रूप में है। फिलहाल के हालातों को देखते हुए वैश्विक जोखिम से खुद को बचाने के लिए भारत तेजी से ये कदम उठा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ छह महीने में ही 104.23 टन सोना देश में वापस लाया गया है। बता दें कि मार्च 2023 तक हमारा केवल 37 प्रतिशत सोना ही देश में था। ये तेजी बताती है कि भारत अब किसी भी तरह के बाहरी जोखिम को हल्के में नहीं ले रहा है। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा अफगानिस्तान और रूस के रिजर्व फंड पर रोक लगाने जैसी घटनाओं ने पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंकों की नींद उड़ा दी है। दुनिया को यह समझ आ गया है कि दूसरे देशों में रखी संप्रभु संपत्ति पूरी तरह से राजनीतिक फैसलों से सुरक्षित नहीं है। आज के टूटते वैश्विक मौद्रिक तंत्र में अगर सोना आपके सीधे कब्जे में नहीं है तो वह वास्तव में आपका है ही नहीं। भारत का यह कदम एक तरह का 'स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस' है। संकट के समय तरलता (लिक्विडिटी) के लिए यह तभी काम आएगा जब यह हमारी अपनी पहुंच में होगा। ऐसे में भारत विदेशों में जमा अपना सोना तेजी से वापस ला रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देश भी विदेशी जोखिमों से बचने के लिए अपना सोना वापस मंगा रहे हैं। फ्रांस 2026 की शुरुआत में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व से 129 टन सोना वापस पेरिस ले आया। जर्मनी न्यूयॉर्क में रखे अपने 1,236 टन सोने की सुरक्षा को लेकर विचार कर रहा है। टूटती वैश्विक व्यवस्था के मौजूदा दौर में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक मानने लगे हैं कि अगर सोना उनके पास नहीं है तो ये उनका सोना नहीं है। मौजूदा सोने के मूल्य पर बैंक ऑफ इंग्लैंड को सालाना लगभग 10 करोड़ डॉलर यानी 950 करोड़ रुपये के आसपास की कस्टडी फीस देनी पड़ती थी। ये पैसा अब नहीं देना पड़ेगा। भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सोना सीधे उपलब्ध होगा। आरबीआई जरूरत पड़ने पर इसे रुपये की कीमत के लिए या स्वैप के माध्यम से डॉलर जुटाने के लिए तत्काल इस्तेमाल कर सकेगा। आज से 35 साल पहले खाड़ी युद्ध के समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्ते के आयात के बराबर भी नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से 7 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा। इसके लिए भारत के स्वर्ण भंडार से 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड ले जाना पड़ा जबकि 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड चार्टर्ड विमान से ये सोना भेजा गया था। उस वक्त भारत का सोने का भंडार केवल 333 टन था। यानी 20 प्रतिशत सोना गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड, वही स्विट्जरलैंड, जहां भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा लेकिन 2026 में युद्ध के हालात में भी भारत विदेश से अपना सोना वापस ला रहा है। उसी बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकाल रहा है, जिसके पास सोना गिरवी रखने की मजबूरी आई थी। उस वक्त सिर्फ 1 अरब डॉलर के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के आसपास है। यानी 700 गुना ज्यादा। 2026 में सोना वापस लाना भारत के लिए गर्व की बात है। इसीलिए हम इसे देश का गोल्डन डिसीजन कह रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

रणबीर कपूर ने अयोध्या में 3.31 करोड़ की जमीन खरीदी- रामायण में निभाएंगे भगवान राम का रोल, अमिताभ ने भी किया था निवेश

एक्टर रणबीर कपूर ने अयोध्या के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'द सरयू' में जमीन खरीदी है। यह प्रोजेक्ट द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा का प्रीमियम प्लॉटिड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। न्यूज एजेंसी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, यह डील 3.31 करोड़ रुपए में हुई है। खरीदी गई जमीन का कुल क्षेत्रफल 2,134 वर्ग फीट है। अमिताभ बच्चन के बाद द सरयू में निवेश करने वाले रणबीर कपूर दूसरे बड़े एक्टर बने हैं। 'द सरयू' 75 एकड़ में फैला प्रोजेक्ट है, जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। इस प्रोजेक्ट में ग्रैंड क्लब हाउस, 35 से यादा लाइफस्टाइल सुविधाएं और द लीला होटल्स का पांच एकड़ में बनने वाला शुद्ध शाकाहारी लग्जरी होटल शामिल है।

रणबीर बोले- अयोध्या ने मुझे चुना

रणबीर ने बयान में कहा कि उन्हें लगता है कि अयोध्या ने उन्हें चुना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है और 'द सरयू' में यह जमीन उनके परिवार की विरासत का हिस्सा बनेगी। HoABL के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने कहा कि अयोध्या सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिम और दुनिया भर का ध्यान खींचने की वजह से शहर में लंबे समय तक विकास की संभावना है। उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर का इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि खरीदार अयोध्या को न केवल इमोशनली बल्कि भविष्य के नजरिए से भी एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि यह इन्वेस्टमेंट ऐसे समय में सामने आया है, जब रणबीर डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर फिल्म से रणबीर का भगवान राम के रूप में लुक भी सामने आया था।

फिल्म रामायण से जुड़ी अहम बातें-

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे। 1987 के टीवी शो 'रामायण' में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस फिल्म में राजा दशरथ की भूमिका में दिखेंगे।

फिल्म का कुल बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल करता है।

फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म दंगल बनाई थी।

फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान और हॉलीवुड कंपोजर हैंस जिमर तैयार कर रहे हैं। फिल्म को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स बना रहे हैं। फिल्म IMAX पर रिलीज होगी।

फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स का काम ऑस्कर विनर स्टूडियो DNEG और प्राइम फोकस संभाल रहे हैं। फिल्म को दो भागों में रिलीज किया जाएगा। पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

जावेद जाफरी की पत्नी से 16 करोड़ की ठगी-मुख्य आरोपी गिरफ्तार; बीएमसी कमिश्नर समेत 6 पर केस, घर आकर की फर्जी रजिस्ट्री

मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा जाफरी से हुई 16.24 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हाई-प्रोफाइल केस में बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर महेश पाटिल समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपियों ने टैक्स सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर जाफरी परिवार को अपनी साजिश में फंसाया।

बीएमसी नोटिस से हुई ठगी की शुरुआत

ठगी की शुरुआत अप्रैल 2024 में हुई। हबीबा जाफरी को उनके अंधेरी स्थित बंगले का प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए बीएमसी से एक नोटिस मिला। इसी दौरान एक परिचित के जरिए उनकी मुलाकात बीएमसी जी-साउथ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर महेश पाटिल से हुई। पाटिल ने पहले टैक्स सेटलमेंट का भरोसा दिया और फिर उन्हें बांद्रा (पश्चिम) के न्यू कमलकुंज कमर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करने का लालच दिया।

भरोसा जीतने के लिए दिखाई फर्जी रिपोर्ट्स

असिस्टेंट कमिश्नर ने हबीबा की मुलाकात कारोबारी निशित पटेल से कराई। निशित ने खुद को बड़े बिल्डरों का पार्टनर बताया और दावा किया कि इस प्रोजेक्ट में पहले से 150 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। जाफरी परिवार का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने घर जाकर नक्शे, फर्जी लेटरहेड और विदेशी बैंकों के साथ प्री-लीज एग्रीमेंट के कागजात दिखाए। उन्होंने वादा किया कि दिसंबर 2025 तक उन्हें कमर्शियल स्पेस का कब्जा मिल जाएगा।

घर पर की फर्जी रजिस्ट्री

साजिश को असली दिखाने के लिए आरोपी रूपेश, देवेंद्र पडवल और उनके साथी सरकारी मशीनों जैसी डिवाइस लेकर जाफरी परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने घर पर ही हबीबा के फोटो, फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर लिए और दावा किया कि सरकारी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

बाद में उन्हें दस्तावेजों की फोटोकॉपी थमा दी गई। जब असली कागजात मांगे गए, तो बिल्डर के पास होने का बहाना बनाया गया।

फ्लैट और बंगला बेचकर जुटाए 16.24 करोड़

आरोपियों के झांसे में आकर जावेद जाफरी, उनकी पत्नी हबीबा और भाई नावेद जाफरी ने अपनी संपत्तियां बेचकर पैसा जुटाया। पुलिस के मुताबिक, यह रकम पूजन टेक्नोलॉजीज, उदित ट्रेडर्स और एशियन फूड जैसी शेल कंपनियों के खातों में ट्रांसफर की गई। कुल 16.24 करोड़ की ठगी में कैश के अलावा विदेशी करेंसी और एक लग्जरी घड़ी भी शामिल है।

निशित 19 मई तक पुलिस रिमांड पर

धोखाधड़ी का अहसास होने पर हबीबा जाफरी ने खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने निशित पटेल को पकड़ लिया। निशित ने पूछताछ में फर्जी दस्तावेज तैयार करने की बात कबूल ली है। कोर्ट ने उसे 19 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब फरार चल रहे असिस्टेंट

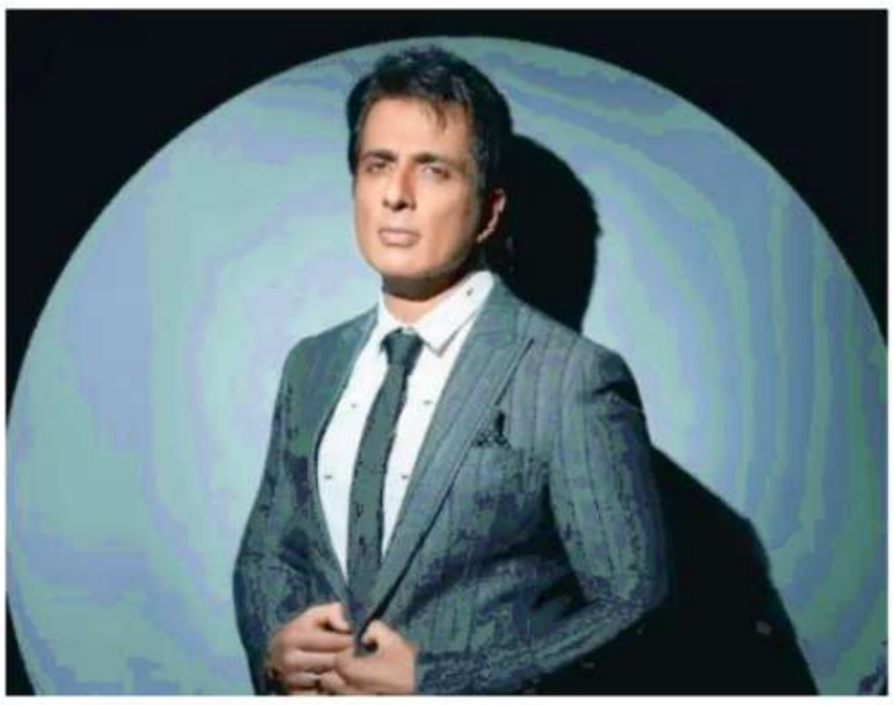

रजनीकांत ने सुनाया बेंगलुरु आश्रम से जुड़ा वो किस्सा, जिसने चूर-चूर कर दिया था उनके सुपरस्टार होने का अहंकार

मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने हाल ही में बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर की अपनी एक पुरानी यात्रा का दिलचस्प किस्सा साझा किया। आश्रम के 45 साल पूरे होने और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने बताया कि कैसे एक आध्यात्मिक यात्रा ने उनके सुपरस्टार होने के अहंकार को पूरी तरह खत्म कर दिया। रजनीकांत ने कहा कि हिमालय के बाद यह आश्रम उनकी सबसे पसंदीदा जगह बन गई है। रजनीकांत ने बताया कि जब वे पहली बार आश्रम पहुंचे, तो वहां की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और मुस्कुराते हुए लोगों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने केवल दो दिन रुकने का मन बनाया था, लेकिन वहां का माहौल ऐसा था कि वे 15 दिनों तक वहीं रुक गए। उन्होंने मजाक में यह भी बताया कि आश्रम में एक घोड़े का नाम भी रजनी था, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। अभिनेता ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसने उन्हें जीवन की सचाई दिखाई। उन्होंने बताया कि एक बार श्री श्री रविशंकर ने उन्हें दर्शन के लिए साथ चलने को कहा। रजनीकांत को डर था कि एक बड़ा स्टार होने के नाते लोग उन्हें घेर लेंगे और ऑटोग्राफ मांगेंगे। वहां सैकड़ों लोग थे, जिनमें कई तमिलनाडु से भी थे। लेकिन रजनीकांत यह देखकर हैरान रह गए कि किसी एक व्यक्ति ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। रजनीकांत ने कहा, मैं लोगों को हाथ हिला रहा था, लेकिन कोई मुझे देख ही नहीं रहा था। सब अपनी भक्ति में लीन थे। इस अनुभव ने मेरे अहंकार को चूर-चूर कर दिया। उन्होंने मंच से स्वीकार किया कि फिल्मी स्टारडम अस्थाई है और कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि असली और स्थायी स्टारडम आध्यात्मिकता में है, जो इंसान की मृत्यु के बाद भी बढ़ता रहता है। उन्होंने श्री श्री रविशंकर को गुरुदेव कहते हुए इस गहरे सबक के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

ट्रोलिंग पर आलिया भट्ट के सपोर्ट में आए सोनू सूदत- कांस में इग्नोर होने के दावों पर बोले- अपनों की कमियां मत निकालो, मेहनत पर गर्व करो

एक्ट्रेस आलिया भट्ट कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा।

कुछ वीडियो वायरल होने के बाद दावा किया गया कि इंटरनेशनल पैपराजी ने उन्हें इग्नोर किया। अब एक्टर सोनू सूद आलिया के समर्थन में उतरे हैं।

सोनू ने लोगों से अपील की है कि वे इंटरनेशनल स्टेज पर भारतीय कलाकारों का हौसला बढ़ाएं, न कि उनकी कमियां ढूंढें।

सोनू सूद बोले- कांस में खड़ा होना ही बड़ी उपलब्धि

सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर किया है। हालांकि उन्होंने पोस्ट में सीधे तौर पर आलिया का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस इसे आलिया के सपोर्ट में देख रहे हैं। सोनू ने लिखा, जब हमारा कोई इंटरनेशनल स्टेज पर जाता है, तो यह गर्व का पल होना चाहिए, कमियां निकालने का नहीं। हर उपलब्धि को कैमरों, हेडलाइंस या

अजनबियों की वाहवाही की जरूरत नहीं होती। वहां खड़े होकर ग्रेस के साथ अपने क्राफ्ट का प्रतिनिधित्व करना ही बड़ी उपलब्धि है।

दूसरों को नीचे गिराने वालों के पास सपने नहीं होते

सोनू ने ट्रोलिंग कल्चर पर तंज कसते हुए आगे लिखा, आज की दुनिया को ट्रोल करने की लत लग गई है, लेकिन आप दूसरों का हौसला बढ़ाना चुनें। जो लोग अपने सपने पूरे करने में बिजी होते हैं, उनके पास दूसरों को नीचे गिराने का वक्त नहीं होता। चमकते रहो मेरे दोस्त, जिन्हें तुम्हारी रोशनी देखनी थी उन्होंने देख ली।

आलिया ने भी ट्रोल को दिया मजेदार जवाब

इससे पहले आलिया ने भी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक ट्रोल को जवाब दिया था। एक यूजर ने आलिया की आइवरी साड़ी वाली फोटो पर कमेंट किया था- कितने दुख की बात है, वहां किसी ने आपको नोटिस ही नहीं किया। इस पर आलिया ने शांति और शालीनता से जवाब दिया, दुख कैसा प्यार? आपने तो मुझे नोटिस किया ÷।

अली गोनी और राहुल वैद्य ने भी उठाई आवाज

आलिया के सपोर्ट में केवल सोनू सूद ही नहीं, बल्कि टीवी एक्टर अली गोनी और सिंगर राहुल वैद्य भी सामने आए।

अली गोनी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि यह देखना दुखद है कि जब कोई भारत को ग्लोबल लेवल पर रिप्रजेंट कर रहा है, तो हमारे अपने ही लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं।

राहुल वैद्य ने भी लोगों से भारतीय कलाकारों के प्रति दयालु रहने की अपील की।

लगातार दूसरी बार कांस पहुंचीं आलिया

आलिया भट्ट ने इस साल लगातार दूसरी बार कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने 2025 में यहां अपना डेब्यू किया था। इस साल आलिया ने भारत पैवेलियन के लिए आइवरी सिल्क साड़ी-गाउन और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए सिंड्रेला स्टाइल का ब्लू गाउन चुना था।

ऊषा उत्थुप ने वायरल पोस्ट पर सफाई दी- सिंगर ने 'दीदी' गाने को ममता बनर्जी की चुनावी हार से जोड़ने के दावों को गलत बताया

वेटरन सिंगर ऊषा उत्थुप ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट पर रिएक्ट किया, जिसमें उनके एक गाने को ममता बनर्जी की हालिया चुनावी हार से जोड़ा गया। सिंगर ने इन दावों को गलत बताया। दरअसल, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ङ्क पर एक यूजर ने उत्थुप का बंगाली गाना दीदी गाते हुए वीडियो शेयर किया। पोस्ट में दावा किया गया कि सिंगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार का जश्न मना रही हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया कि ङ्कस्ट शासन के दौरान उनके कार्यक्रमों के लिए कट मनी मांगी जाती थी, जिसके कारण वह कोलकाता छोड़कर मुंबई चली गई थीं। यूजर ने लिखा कि अब वह वापस लौट आई हैं। इन दावों पर रिएक्ट करते हुए ऊषा उत्थुप ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर मेरे बारे में एक पोस्ट वायरल हो रही है। मैं साफ करना चाहती हूं कि उस पोस्ट में कही गई कई बातें गलत और भ्रामक हैं। जिस गाने की बात हो रही है, वह एक बंगाली गाना है। इसे कई साल पहले बनाया गया था और यह एक अरबी धुन से प्रेरित है। मैं पिछले 20 सालों से इसे सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति के तौर पर गाती आ रही हूं।' सिंगर ने आगे लिखा, 'मैं यह भी साफ करना चाहती हूं कि मैं 1976 से कोलकाता में रह रही हूं। मैंने कभी कोलकाता छोड़कर मुंबई शिफ्ट नहीं किया। कोलकाता हमेशा मेरा घर रहा है और मैं आज भी यहां के लोगों और इस शहर से बहुत प्यार करती हूं।' पोस्ट के अंत में ऊषा उत्थुप ने लिखा, 'उस पोस्ट में जो बातें, टिप्पणियां और कहानियां फैलाई जा रही हैं, उनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। मैं उनसे खुद को नहीं जोड़ती और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। कृपया मुझे बेवजह ऐसे विवादों में न घसीटें, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ढेर सारा प्यार, दीदी (ऊषा उत्थुप)।' गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। पार्टी ने 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 207 सीटें जीतीं, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई। पार्टी की सीटों की संख्या 215 से घटकर 80 हो गई और ममता बनर्जी भी अपनी भवानीपुर सीट हार गईं। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त- केंद्र से कहा- मनमानी कीमतों पर लगाएं लगाम, यात्रियों को दें बड़ी राहत

नई दिल्ली। देश में हवाई टिकटों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि हवाई किराए का युक्तीकरण होना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह हवाई यात्रियों को किराए की विसंगतियों से राहत दिलाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एयरलाइंस के कामकाज पर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि एक ही दिन और एक ही सेक्टर के लिए अलग-अलग एयरलाइंस अलग-अलग किराया वसूल रही हैं। कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही रूट पर एक एयरलाइन 8,000 रुपये ले रही है, तो दूसरी उसी इकोनॉमी क्लास के लिए 18,000 रुपये वसूल रही है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, किराए के इस भारी अंतर को दूर कर जनता को राहत देने का प्रयास करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 प्रभावी हो चुका है। इसके तहत नए नियम बनाने के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। सरकार इस समस्या को केवल कानूनी लड़ाई के तौर पर नहीं देख रही है।

आरजी कर केस पर एक्शन में शुभेंदु सरकार, 3 अधिकारियों पर गिरी गाज, नौकरी से सस्पेंड

बंगाल । आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेज और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले की शुरुआती जांच के दौरान कथित लापरवाही के आरोप में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, पूर्व डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के मद्देनजर निलंबित करने का आदेश दिया गया है. सीएम शुभेंदु ने कहा कि तीनों अधिकारी मामले को लापरवाहीपूर्ण तरीके से संभालने में कथित तौर पर शामिल थे. उन्होंने पीड़िता के माता-पिता को रिश्वत के रूप में पैसे की पेशकश की थी और अगस्त 2024 में हुए इस जघन्य अपराध के संबंध में एक अनाधिकृत प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया था. शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपराध की वास्तविक जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच का नेतृत्व राय के गृह सचिव मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में करेंगे.

पीड़िता की मां ने बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प लिया

आरजी कर रेप-हत्या मामले में पीड़िता की मां और पानीहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रत्ना देबनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करना उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई का पहला निर्णायक कदम है. 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में रेप के बाद देबनाथ की बेटी की हत्या कर दी गई थी. विधानसभा परिसर में देबनाथ ने कहा कि उनकी लड़ाई में एक अहम मोड़ तब आया जब वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ हुई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शामिल होने राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचीं. उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. उन्होंने कहा, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस अपराध के दोषियों को सजा न मिल जाए और घर, कार्यस्थल या बाहर निकलने वाली हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस न करे और आरजी कर मामले समेत ऐसे सभी मामलों के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा न मिले.

मुबारकपुर डबास में वाल्मीकि समाज के लिए नई उम्मीद- Tiger Group करेगा मंदिर का पुनर्निर्माण

नई दिल्ली, (ए.के. चौधरी) मुबारकपुर डबास गांव में वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़े वाल्मीकि मंदिर को अब नई पहचान मिलने जा रही है। मंदिर के पुनर्निर्माण और विकास की जिम्मेदारी Tiger Group ने उठाई है। इस पुण्य कार्य की शुरुआत अजय चौधरी उर्फ अंजू भाई ने 50,000 रुपये की सहयोग राशि देकर की। उनके इस कदम के बाद समाज के युवाओं में नया उत्साह देखने को मिला।

Tiger Group के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक परचा के नेतृत्व में समाज के युवा लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुटे हैं। मंगलवार को समूह के सभी सदस्य मंदिर स्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज को भरोसा दिलाया कि यह मंदिर केवल भवन नहीं, बल्कि समाज के सम्मान, एकता और संस्कृति का प्रतीक बनेगा। स्थानीय लोगों ने Tiger Group के प्रयासों की सराहना की। समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें इन युवाओं पर गर्व है जो निस्वार्थ भाव से समाज और धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं।

कुछ बेरोजगार युवा तिलचट्टों की तरह हैं, जो व्यवस्था पर हमले करते हैं, शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने शुक्रवार को कुछ बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे तिलचट्टों जैसे हैं, जो आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं। फिर व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। यह टिप्पणी उस समय आई ,जब मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वकील ने वरिष्ठ वकील का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में पहले से ही कुछ ऐसे परजीवी मौजूद हैं, जो व्यवस्था पर लगातार हमला करते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता वकील से कहा, पूरी दुनिया वरिष्ठ (वकील) बनने के योग्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आप तो इसके हकदार नहीं हैं। सीजेई ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट याचिकाकर्ता को वरिष्ठ वकील का पदनाम प्रदान करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उनके पेशेवर आचरण को देखते हुए इसे रद्द कर देगा। सीजेआई ने फेसबुक पर याचिकाकर्ता की ओर से इस्तेमाल की गई भाषा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी हैं, जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, कई युवा तिलचट्टों की तरह हैं, जिन्हें न तो कोई नौकरी मिलती है और न ही पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बन जाते हैं। कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करने लगते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या उसके खिलाफ कोई अन्य मुकदमा नहीं है। पीठ ने पूछा, क्या यह उस व्यक्ति का आचरण है जो वरिष्ठ वकील के रूप में नामित होना चाहता है? कोर्ट ने कहा, वरिष्ठ वकील का पदनाम एक ऐसी चीज है, जो किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है और इसके लिए प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या वरिष्ठ वकील का पदनाम एक प्रतिष्ठा प्रतीक है, जिसे केवल दिखावे के लिए रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या यह उचित प्रतीत होता है? कोर्ट ने पाया कि वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कहना चाहता है कि वह काले कपड़े पहनने वाले कई लोगों की डिग्री सत्यापित करे, क्योंकि उनकी डिग्री के असली होने पर गंभीर शक है। पीठ ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें उनके वोटों की जरूरत है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पीठ से माफी मांगी और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। फिर पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

अशोका एक्सप्रेस की वेबसाईट से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र
प्रिय पाठक, विज्ञापन दाता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप्प या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री मुख्यस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखों को न भेजें।
संपादक: विजय कुमार
Website: https://ashokaexpress.com/, Email: ashoka.express@live.com, Mobile No. 9810614206
अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं।
Account Holder Name: ASHOKA EXPRESS
Bank Account No.: 10650995502 & 41856402452
IFSC Code: SBIN0004646
UPI ID: 9810674206@sbi

राहुल के विदेश दौरों पर केंद्रीय मंत्री ने उठाया सवाल, कहा- संसद में बिना बताए करते हैं यात्रा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के यात्राओं पर सवाल किया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बिना सूचना दिए विदेश यात्रा करना गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सांसद को अपनी यात्रा के बारे में 3 सप्ताह पहले सूचना देना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी की बिना सूचना के विदेश यात्रा गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रत्येक सांसद को अपनी विदेश यात्रा से 3 सप्ताह पहले लोकसभा और रायसभा सचिवालय को सूचित करना अनिवार्य है। यह अनुमति नहीं बल्कि सूचना है। सांसद विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सूचना देना आवश्यक है।

भारत से बाहर कितने दिन रहे?

अगर कोई सांसद विदेश में आतिथ्य सत्कार स्वीकार करता है, तो उसे आमंत्रित करने वाली एजेंसियों या संगठनों द्वारा वहन किया जाने वाला खर्च एफसीआरए के अंतर्गत आएगा। राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं और उनकी 54 विदेश यात्राएं दर्ज की गई हैं। यह केवल 54 यात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि वे भारत से बाहर कितने दिन रहे और उन्होंने कितना खर्च किया।

विदेश यात्राएं क्यों की, जानकारी दे

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मेरा अनुरोध है कि वह नियमों का पालन करें और अधिकारियों को आवश्यक जानकारी दें। उन्हें प्रस्तावित विदेश यात्रा से 3 सप्ताह पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना होगा। अगर उन्हें विदेश में आतिथ्य सत्कार स्वीकार करना है, तो उन्हें एफसीआरए के तहत गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा। इसलिए, मैं राहुल गांधी से अनुरोध करता हूं कि वे स्पष्ट करें कि उन्होंने इतनी विदेश यात्राएं क्यों की हैं।

देश के कानूनों का पालन करना चाहिए-रिजिजू

उन्होंने आगे कहा यात्रा करना उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि उन्हें किसने आमंत्रित किया है। भारत के बाहर की एजेंसियों/संगठनों ने उनके नाम पर क्या खर्च किए है? मेरा मानना है कि हर भारतीय को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। खासकर सांसदों को।

अगर कुछ होता है, तो कोई कार्रवाई शुरू की जाती है। राहुल गांधी या किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कानून सबके लिए है।

पहली बार दिल्ली में हाइड्रोजन बसें, जानें कहां से कहां तक चलेंगी, कितना होगा किराया?

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पहली बार, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली मेट्रो को दो ऐसी अत्याधुनिक बसें सौंपी हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 15 मई यानी आज से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक एकीकृत हाइड्रोजन चालित शटल बस सेवा शुरू की। यह पहल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है। यह सेवा अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायक होगी। इन बसों में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग और सीसीटीवी प्रणाली लगी होगी। यह वास्तविक समय की निगरानी, सुरक्षा और समयबद्धता सुनिश्चित करेगी। यह शटल सेवा सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार, राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर) में चलेगी। सेवा का समय सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा।

कनेक्टिविटी और मार्ग

यह सेवा सेंट्रल सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका लक्ष्य सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित प्रमुख सरकारी कार्यालयों को भी जोड़ना है। यह सरकारी अधिकारियों और आम जनता को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। यह सेवा कार्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर सड़क और बड़ौदा हाउस जैसे प्रमुख स्थलों को कवर करेगी। नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स और इंडिया गेट भी इस मार्ग में शामिल होंगे। डीएमआरसी बस संचालन, कंडक्टर, टिकटिंग और यात्री सहायता की जिम्मेदारी संभालेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ड्राइवरों की व्यवस्था करेगा। साथ ही वह हाइड्रोजन ईंधन सहायता भी उपलब्ध कराएगा। सेवा की फ्रीक्वेंसी हर 30 मिनट पर एक बस होगी। एक बस दक्षिणावर्त और दूसरी वामावर्त दिशा में चलेगी। किराया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यूपीआई और नकद भुगतान के माध्यम से लिया जाएगा। इसमें 10 रुपये और 15 रुपये की किफायती स्टेज आधारित टिकट दरें निर्धारित हैं। यह पहल भारत सरकार की हरित गतिशीलता और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन ढांचे के प्रति सरकार के समर्पण का प्रतीक है। यह परियोजना भविष्य में पूरे देश में हाइड्रोजन आधारित परिवहन प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में देखी जा रही है। यह भारत के शहरी परिवहन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। इसका लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करना है। यह पहल टिकाऊ शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज, अमित शाह पर टिप्पणी और भड़काऊ बयानों के आरोप

नई दिल्ली । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए भड़काऊ और विवादित भाषणों को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली है। यह मामला सीधे तौर पर चुनाव के दौरान माहौल खराब करने और देश के गृह मंत्री को धमकी देने के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। आरोप है कि इन रैलियों में उन्होंने बेहद आक्रामक और भड़काऊ भाषण दिए थे। इसी मामले में उनके खिलाफ विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि उनके भाषणों से समाज में नफरत फैल सकती थी और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती थी। इसके अलावा, उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरे शब्द इस्तेमाल करने का भी बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है।

शिकायत किसने दर्ज कराई?

टीएमसी नेता के खिलाफ यह अहम शिकायत राजीव सरकार नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई है। राजीव सरकार ने चुनाव के नतीजे आने के ठीक एक दिन बाद यानी पांच मई को बागुईहाटी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपनी बात साबित करने के लिए अभिषेक बनर्जी के कई विवादित भाषणों के वीडियो लिंक भी सबूत के तौर पर सौंपे हैं। इन्ही सबूतों के आधार पर पुलिस ने आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?

पुलिस ने इस पूरी शिकायत की जांच करने के बाद 15 मई को दोपहर 2.45 बजे विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई सख्त धाराओं जैसे 192, 196, 351(2) और 353(1)(ठ) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 भी लगाई गई है। पुलिस की एफआईआर में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया था।

एफआईआर में क्या गंभीर बातें?

पुलिस की एफआईआर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी के भाषणों में ऐसी भड़काऊ और धमकी भरी बातें थीं, जो समाज में सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने और सांप्रदायिक सौहार्द (भाईचारा) बिगाड़ने की क्षमता रखती थीं। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर सोमनाथ सिंघा रॉय को सौंपी है।

अब जेल में हर पार्सल पर नजर, एसओपी से बढ़ी जवाबदेही; जेल मुख्यालय ने जारी की नई मानक संचालन प्रक्रिया

नई दिल्ली । दिल्ली की जेलों में कैदियों को मिलने वाले पार्सल को लेकर अब जेल प्रशासन की मनमानी और प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं पर लगाम लगने जा रही है। जेल मुख्यालय ने नई मानक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है। इसमें कहा कि पार्सल की जांच, रिकॉर्डिंग और वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह होगी। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब किसी भी पार्सल को बिना ठोस कारण के रोकना या उसमें देरी करना आसान नहीं होगा। जेल प्रशासन ने साफ कहा कि पार्सल से जुड़े हर फैसले का लिखित रिकॉर्ड रखा जाएगा। जेल के अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जेल में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कैदियों तक पार्सल पहुंचाने की प्रक्रिया में देरी होती है। कई मामलों में सुरक्षा जांच के नाम पर पार्सल लंबे समय तक लंबित रखे जाते थे, जिससे कैदियों और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ती थी। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए जेल मुख्यालय की ओर से नई एसओपी लागू करने का फैसला लिया। दिशा निर्देशों के मुताबिक जेल के उपाधीक्षक की मौजूदगी में पार्सल को खोलकर इसकी जांच होगी। पहले जेल के छोटे कर्मचारी इस काम को करते थे। इसके साथ ही जेल के वेलफेयर अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी है कि वह हर सप्ताह पार्सल रजिस्टर की जांच करेंगे। उन्हें यह भी देखना होगा कि किसी भी कैदी को उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर सुविधा से वंचित न किया जाए। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक पार्सल को सुरक्षा कारणों से रोकने पर जेल अधीक्षक को स्पष्ट कारण लिखित रूप से देना होगा। इसके साथ ही पार्सल में तंबाकू, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलती हैं, तो उन्हें तुरंत जब्त कर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही पार्सल को एक्स-रे स्कैन कराया जाएगा। पार्सल में आने वाली सभी वस्तु एक रजिस्टर में दर्ज होगा। इससे सामान के गायब होने, बदलने या विवाद की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाएगी। दिशा निर्देश में कहा गया है कि नियम तोड़ने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।

दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे कम बढ़े तेल के दाम

नई दिल्ली । भारत में तेल-गैस की कीमतों में इजाफा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। भाजपा नेताओं ने भारत और अन्य देशों में तेल कीमतों में बढ़ोतरी की तुलना की। साथ ही, दावा किया कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत वह देश रहा है, जहां आम नागरिकों पर सबसे कम बोझ पड़ा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को हर चीज का राजनीतिकरण करने पर शर्म आनी चाहिए। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने और तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण अप्रैल और मई के अधिकांश समय ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रहा। इसका असर दुनिया की लगभग हर अर्थव्यवस्था में सीधे पेट्रोल पंपों पर दिखाई दिया। लेकिन भारत इस पूरी तस्वीर में एक अलग और उल्लेखनीय अपवाद बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी से 15 मई के बीच अधिकांश देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अमित मालवीय के अनुसार, अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 44.5 प्रतिशत बढ़ीं और डीजल की कीमतों में 48.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 54.9 प्रतिशत और डीजल के दाम 44.9 प्रतिशत बढ़े हैं। ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमत में 19.2 प्रतिशत और डीजल की कीमत में 34.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अमित मालवीय ने बताया कि जर्मनी में पेट्रोल के दाम 13.7 प्रतिशत और डीजल के दाम 19.8 प्रतिशत बढ़े, जबकि जापान में पेट्रोल की कीमत 9.7 प्रतिशत और डीजल 11.2 प्रतिशत बढ़ी।

भाजपा नेता ने यह भी बताया कि म्यांमार में पेट्रोल की कीमत में सबसे अधिक 89.7 प्रतिशत और डीजल की कीमत में 112.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। भाजपा नेता ने कहा कि इन देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल के सबसे कम दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा, भारत में वृद्धि सबसे कम रही, जहां पेट्रोल की कीमत में 3.2 प्रतिशत और डीजल की कीमत में 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, केवल सऊदी अरब में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष सरकारी सब्सिडी व्यवस्था लागू है। लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत वह देश रहा जहां आम नागरिकों पर सबसे कम बोझ पड़ा। यह अपने आप नहीं हुआ।

भाजपा नेता ने सरकार की तारीफ क्यों की?

अमित मालवीय ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, पश्चिम एशिया संकट गहराने के बाद पूरे 76 दिनों तक भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों, जिनकी खुदरा बाजार में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ सीधे जनता पर नहीं डाला। उन्होंने स्वयं लागत का बड़ा हिस्सा वहन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रतिदिन लगभग 1000 करोड़ रुपए तक की अंडर-रिकवरी हो रही थी। भाजपा नेता ने कहा कि 15 मई को घोषित 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि लगभग चार वर्षों में पहली बढ़ोतरी है और यह करीब 95 रुपए प्रति लीटर के आधार मूल्य पर सिर्फ लगभग 3.5 प्रतिशत की वृद्धि बैठती है। बाकी दुनिया से तुलना कीजिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में लोग तीन महीने पहले की तुलना में लगभग 55 प्रतिशत अधिक कीमत चुका रहे हैं, जबकि मलेशिया में 56 प्रतिशत और अमेरिका में लगभग 45 प्रतिशत अधिक कीमत चुका रहे हैं। कई देशों में डीजल की कीमतें 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं, क्योंकि डीजल सीधे माल ढुलाई, व्यापार और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा है। अमित मालवीय ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने दो महीने से अधिक समय तक वैश्विक तेल संकट का असर आम नागरिकों तक पहुंचने से रोके रखा और अभी भी केवल सीमित व संतुलित वृद्धि की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पेट्रोल पंप की कीमतों का मामला नहीं है।

तमकुहीराज में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका

कुशीनगर।

जनपद के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के शिवसरया बुजुर्ग गांव में शुक्रवार सुबह एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार 15 मई 2026 को सुबह करीब सात बजे डायल 112 को सूचना मिली कि ग्राम शिवसरया बुजुर्ग में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना मृतका के भतीजे सूरज शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम तुर्कपट्टी महुआ सूर्य मंदिर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर द्वारा दी गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक तमकुहीराज गिरजेश उपाध्याय तथा चौकी प्रभारी समउर अखिलेश कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान अंजली शर्मा पत्नी कमलेश शर्मा निवासी शिवसरया बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर, उम्र लगभग 30 वर्ष, के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अंजली शर्मा ने घर की छत पर लगे एंगल में दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। घटना के बाद परिजनों ने शव को नीचे उतारकर आंगन में रख दिया था। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है। पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार मृतका का व्यवहार सामान्य था, जिससे घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक तमकुहीराज गिरजेश उपाध्याय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

स्वर्णकार समाज ने जताई चिंता: रोजगार प्रभावित करने वाले फैसलों पर व्यापक चर्चा की मांग

रवि वर्मा

बृजेश वर्मा

अनिरुद्ध वर्मा

आनन्द वर्मा

दीपक वर्मा

भटनी बाजार।

स्वर्णकार समाज के लोगों ने हाल के स्वर्ण कारोबार से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देशहित सर्वोपरि है, लेकिन ऐसे किसी भी निर्णय से बचना चाहिए जिससे लाखों स्वर्णकार परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो। समाज के लोगों ने सरकार से स्पष्ट नीति और वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करने की मांग की। समाज के लोगों का कहना है कि यदि सोने की वैश्विक कमी की आशंका है तो बड़े स्तर पर होने वाले गोल्ड निवेश, आयात और कॉर्पोरेट कारोबार की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए, न कि छोटे व्यापारियों और आम ग्राहकों को प्रभावित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार मुख्य रूप से पुराने आभूषणों के लेन-देन पर आधारित है, इसलिए छोटे ज्वेलर्स पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों पर पुनर्विचार आवश्यक है।

*रवि वर्मा ने स्वर्ण व्यवसायी ने कहा कि देशहित सर्वोपरि है, लेकिन ऐसा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए जिससे स्वर्णकार परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाए।

*बृजेश वर्मा, अध्यक्ष स्वर्ण शक्ति सोसायटी सोनार समाज, ने कहा कि व्यापार और रोजगार को प्रभावित करने वाले फैसलों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

*अनिरुद्ध वर्मा ने कहा कि सरकार को बड़े गोल्ड निवेश और आयात पर नियंत्रण बढ़ाना चाहिए, न कि छोटे व्यापारियों को प्रभावित करना चाहिए।

*आनंद वर्मा ने कहा कि स्थानीय बाजार पुराने आभूषणों के लेन-देन से चलता है, इसलिए छोटे ज्वेलर्स को राहत मिलनी चाहिए।

*दीपक वर्मा कारीगर ने कहा कि स्वर्णकार समाज हमेशा देशहित में खड़ा रहा है, लेकिन सरकार को समाज की आर्थिक सुरक्षा के लिए ठोस नीति और स्पष्ट रोडमैप भी देना चाहिए।

शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में गर्भस्थ शिशु के हृदय रोग का सफल उपचार, जन्म के बाद पूरी तरह स्वस्थ मिला बच्चा

गोरखपुर ।

बाबा गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर अब आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से नई पहचान बना रही है। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में आयोजित एडवांस पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कैंप के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे के हृदय रोग का सफल उपचार शुरू किया गया। जन्म के बाद लगातार निगरानी और आधुनिक जांचों के परिणामस्वरूप आज बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। पीपीगंज निवासी गर्भवती महिला प्रियंका सिंह के गर्भ में पल रहे शिशु की जांच के दौरान हृदय की मुख्य धमनी एओर्टिक आर्च में गंभीर समस्या का पता चला था। इस जानकारी के बाद परिजन अत्यंत चिंतित हो उठे। ऐसे कठिन समय में शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में उपलब्ध उन्नत सुविधाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श ने परिवार को नई आशा दी। मामले की देखरेख डॉ. नीरज अवस्थी ने की, जो स्कॉट फोर्टिस इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी डायरेक्टर एवं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉ. अवस्थी वर्ष 2017 से प्रत्येक माह शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

एडवांस पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कैंप ने गोरखपुर में आधुनिक चिकित्सा की नई उम्मीद जगाई

डॉ. नीरज अवस्थी की देखरेख में 18 माह तक नियमित जांच और उपचार से मिली बड़ी सफलता

उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि नियमित निगरानी, समयबद्ध जांच और उचित उपचार से बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है। जन्म के बाद बच्चे की प्रत्येक छह माह पर इकोकार्डियोग्राफी द्वारा जांच की गई। वर्तमान में बच्चा लगभग 18 माह का हो चुका है।

नवीनतम जांच में उसकी हृदय संबंधी समस्या लगभग पूरी तरह ठीक पाई गई है। यह सफलता न केवल परिजनों के लिए राहत का संदेश है, बल्कि पूर्वांचल में बाल हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के अनुसार डॉ. नीरज अवस्थी के मार्गदर्शन में अब तक लगभग 650 बच्चों के हृदय का निःशुल्क ऑपरेशन सफलतापूर्वक कराया जा चुका है और सभी बच्चे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। यह सेवा उन परिवारों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है, जो बड़े शहरों में महंगा उपचार कराने में असमर्थ होते हैं। अस्पताल में अब लेज़र तकनीक, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और उन्नत कार्डियक सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाएं स्थानीय मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे गोरखपुर और आसपास के जिलों के मरीजों को बड़े महानगरों की ओर जाने की मजबूरी काफी हद तक कम हो रही है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से अब ब्रेन स्ट्रोक, फेफड़ों और किडनी की जटिल समस्याओं, अत्यधिक ब्लीडिंग तथा ऐसे कैंसर जिनका ऑपरेशन संभव नहीं होता, उनके उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। यह चिकित्सा व्यवस्था गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में गर्भस्थ शिशु के हृदय रोग की पहचान, समय रहते उपचार की शुरुआत और जन्म के बाद बच्चे का स्वस्थ होना यह साबित करता है कि सही समय पर जांच, विशेषज्ञ चिकित्सक और आधुनिक तकनीक मिलकर असंभव प्रतीत होने वाली स्थितियों को भी आशा में बदल सकते हैं।

पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में छोटे भाई को मार दी गोली,तीन महीने पहले हुई थी शादी

गोरखपुर । बेलीपार थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। पत्नी से अवैध संबंध के शक में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को गोली मार दी। गोली गले में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। दपुलिस के अनुसार, बेलीपार निवासी धर्मेंद्र पाल के पुत्र रोशन पाल को अपनी पत्नी और छोटे भाई रोहन पाल के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार रात करीब 11 बजे दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान रोशन पाल ने पिस्टल निकालकर छोटे भाई रोहन पाल पर फायर कर दिया। गोली रोहन के गले में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर डायल 112 और बेलीपार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल रोहन को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से आरोपी रोशन पाल को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास अवैध असलहा कहां से आया। इस मामले में गांव के ही दो अन्य युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी रोशन पाल गांव की ही बिरादरी की युवती रुबी को भगाकर लाया था। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से करीब तीन माह पूर्व कौड़ीराम स्थित बगहा वीर बाबा मंदिर में दोनों की शादी कराई गई थी। परिवार में दो भाई रोशन और रोहन तथा एक बहन रोशनी है। घटना के समय घर में मौजूद पत्नी रुबी ने बताया कि वह और रोहन मिट्टी फेंक रहे थे। इसी दौरान रोशन वहां पहुंचा और आते ही पिस्टल निकालकर रोहन को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी रोशन पाल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

सीएम योगी करेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास

गोरखपुर।

शनिवार (16 मई) की तिथि गोरखपुर की उपलब्धियों की श्रृंखला में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने जा रही है। खेल अवस्थापना सुविधाओं के लिहाज से गोरखपुर का नाम वैश्विक स्तर पर उल्लिखित कराने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों हेतु बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। करीब 393 करोड़ रुपये की लागत वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन की तरफ से ताल नदोर में उपलब्ध कराई गई जमीन पर 24 दिसंबर 2025 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। औपचारिक शिलान्यास होने से पूर्व, सरकार की तरफ से जारी परियोजना लागत की प्रथम किश्त 63.39 करोड़ रुपये से काम आगे बढ़ रहा है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड एक (भवन) के अनुसार अब तक करीब सात प्रतिशत काम हुआ है।

स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेशनल स्टेडियम के बन जाने से गोरखपुर आने वाले समय में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए भी जाना जाएगा। गोरखपुर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 46 एकड़ क्षेत्रफल में आकार लेगा। कुल 30 हजार दर्शक क्षमता का यह स्टेडियम 'ग्राउंड प्लस टू फ्लोर' के हिसाब से बनेगा। इसके मेन ग्राउंड पर खिलाड़ियों के लिए 7 प्लेइंग पिच और 4 प्रैक्टिस पिच होगी। स्टेडियम के पूर्वी और पश्चिमी स्टैंड में प्रत्येक में 14,490 दर्शक बैठ सकेंगे। नार्थ पैवेलियन 208 वीआईपी व 382 मीडियाकर्मियों और साउथ पैवेलियन 1708 वीवीआईपी व वीआईपी के लिए होगा। रात्रिकालीन मैच भी हो सकें, इसके लिए मेन स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानक के चार हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था रहेगी।

यहां क्रिकेट के अलावा अन्य बड़े आयोजन भी होंगे। ताल नदोर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतरीन जगह पर है। गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग फोरलेन से जुड़ा यह स्थान, गोरखपुर एयरपोर्ट से करीब 24 किमी की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से करीब 20 किमी है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए यहां पहुंचना काफी सुगम होगा। गोरखपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में देश की शीर्ष पेट्रोलियम कंपनियां अपने सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी) फंड से कुल 100 करोड़ रुपये देंगी। एमओयू के बाद धनराशि आवंटन प्रक्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 60 करोड़ रुपये, भारत पेट्रोलियम 30 करोड़ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10 करोड़ रुपये देगी।

भारत में 5 अरब का निवेश करेगा यूएई; रक्षा, ऊर्जा और गैस सप्लाई पर हुए कई अहम समझौते

अबूधाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की आधिकारिक यात्रा पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों, ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पांच देशों के दौरे पर हैं। इस विदेश दौरे में पीएम मोदी सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर रहे हैं, इसके बाद वे नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के इन दौरों का उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, नवाचार और हरित विकास के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, प्रधानमंत्री नीदरलैंड का दौरा करेंगे। वर्ष 2017 के बाद यह प्रधानमंत्री की नीदरलैंड की दूसरी यात्रा होगी। जॉर्ज ने बताया कि इस यात्रा के दौरान, वे नीदरलैंड के किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर जाएंगे। वहां वे अपने स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देश व्यापार और सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री यूरोपीय उद्योग जगत के बड़े मंच %यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री% को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी मौजूद रहेंगी। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वहां वे तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मंगलवार को इटली जाएंगे। इटली में वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एफ16 जेट विमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया जब वह 15 से 20 मई तक अपनी पांच देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था।

मुथूट फाइनेंस का चौथी तिमाही का मुनाफा दोगुने से भी अधिक होकर 3,397 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। मुथूट फाइनेंस का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 3,397 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में कंपनी ने 1,444 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 9,291 करोड़ रुपए हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 5,627 करोड़ रुपए थी। चौथी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय भी बढ़कर 9,008 करोड़ रुपए रही, जो वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 5,465 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में मुथूट फाइनेंस का शुद्ध लाभ 10,606 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 5,352 करोड़ रुपए था यानी इसमें 98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 31,263 करोड़ रुपए रही, जो 2024-25 में 20,265 करोड़ रुपए थी।

अप्रैल में भारत का निर्यात 13.78फीसदी बढ़कर 43.56 अरब के पार

नई दिल्ली । व्यापारिक मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अप्रैल का महीना मिले-जुले रुझानों वाला रहा है। एक तरफ जहां वैश्विक स्तर पर भारत के कुल निर्यात में शानदार दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया के साथ होने वाले व्यापार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल द्वारा साझा किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कुल निर्यात और आयात दोनों में बढ़ोतरी हुई है, जो घरेलू और बाहरी मांग की गतिशीलता को दर्शाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल के महीने में भारत के कुल निर्यात ने मजबूत प्रदर्शन किया है।

निर्यात- अप्रैल में देश का कुल निर्यात साल-दर-साल आधार पर 13.78 प्रतिशत बढ़कर 43.56 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। यह वृद्धि भारतीय उत्पादों की निरंतर मांग और निर्यातकों के बेहतर प्रदर्शन को रेखांकित करती है।

आयात- दूसरी ओर, आयात के मोर्चे पर भी 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में भारत का कुल आयात बढ़कर 71.94 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 65.38 अरब डॉलर था।

पश्चिम एशिया के मोर्चे पर चुनौती

कुल व्यापारिक आंकड़ों में जहां सकारात्मकता है, वहीं क्षेत्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों में अप्रैल के दौरान सुस्ती दर्ज की गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के बयान के अनुसार, पश्चिम एशिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार के दोनों पैमानों (आयात और निर्यात) में भारी गिरावट आई है।

निर्यात में गिरावट- पश्चिम एशिया को होने वाला भारत का निर्यात 28 प्रतिशत तक लुढ़क गया है। अप्रैल में यह आंकड़ा घटकर 4.16 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 5.78 अरब डॉलर था।

आयात में कमी- इसी तरह, पश्चिम एशिया से होने वाले आयात में भी 31.64 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस साल अप्रैल में यह आयात घटकर 10.47 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 15.32 अरब डॉलर के स्तर पर था।

आगे का आउटलुक

निष्कर्ष के तौर पर, अप्रैल के व्यापारिक आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कुल आयात और निर्यात में क्रमशः 10त्न और 13.78त्न की वृद्धि के साथ अपनी समग्र व्यापारिक क्षमता को मजबूत बनाए रखा है। हालांकि, पश्चिम एशिया के साथ व्यापार में लगभग 30त्न के आसपास की यह गिरावट चिंता का विषय हो सकती है। आगामी तिमाहियों में बाजारों और नीति निर्माताओं की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह क्षेत्रीय गिरावट एक अस्थायी व्यापारिक रुझान है या फिर इसका असर लंबी अवधि के आंकड़ों पर भी देखने को मिलेगा। सरकार की ओर से आयात-निर्यात के आंकड़ों के जारी करने के पूर्व सरकार ने शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3त्न वृद्धि कर दी है। इसके लिए पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण खाड़ी देशों के साथ देश के व्यापार में आए व्यावधान को जिम्मेदार माना जा रहा है।

जेब पर महंगाई की मार पड़ना तय- ईंधन के दाम बढ़ने से माल ढुलाई तीन फीसदी हो सकती है महंगी

कोलकाता ।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब परिवहन क्षेत्र पर भी दिखने लगा है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने कहा कि ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई यानी फ्रेट कॉस्ट में करीब तीन फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि व्यापारी इस बढ़ोतरी का फायदा उठाकर सामानों के दाम जरूरत से ज्यादा न बढ़ाएं। कोलकाता में चारों महानगरों के मुकाबले सबसे ज्यादा ईंधन कीमतों में इजाफा हुआ।

यहां पेट्रोल 3.29 रुपये महंगा होकर 108.74 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि डीजल 3.11 रुपये बढ़कर 95.13 रुपये प्रति लीटर हो गया। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सुनील अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए यह बढ़ोतरी पहले से अनुमानित थी। उन्होंने बताया कि ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई की लागत पर करीब तीन फीसदी असर पड़ेगा। हालांकि, कुल परिवहन लागत पर इसका असर सीमित रहेगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि व्यापारी पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने का बहाना बनाकर सामानों की कीमतों में अनुपातहीन बढ़ोतरी न करें। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रक ऑपरेटर पहले से आर्थिक दबाव में हैं, इसलिए राज्य सरकारें स्थानीय टैक्स और लेवी में राहत देकर कुछ मदद कर सकती हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल ऑनलाइन एप कैब गिल्ड के महासचिव इंद्रनील बनर्जी ने कहा कि ईंधन महंगा होने से कैब ऑपरेटरों पर रोजाना 50 से 60 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने भी राज्य सरकार से टैक्स में राहत देने की मांग की ताकि बढ़ी हुई कीमतों का असर कम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 11 हफ्तों तक ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन लगातार बढ़ती लागत के चलते अब कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी करनी पड़ी।

रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, पहली बार डॉलर के मुकाबले गिरकर 96.07 पर पहुंचा

बिजनेस डेस्क । भारतीय रुपया गुरुवार (15 मई) के कारोबारी सत्र के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपए ने पहली बार डॉलर के मुकाबले 96 का लेवल पार किया। लगातार चौथे दिन रुपए में गिरावट आई। रुपए 96.07 प्रति डॉलर तक फिसल गया, जो अब तक का रिकॉर्ड लो माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी जैसे कारण भी रुपए की कमजोरी की बड़ी वजह बने हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट से आयात महंगा होने और महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। रुपया लगातार गिरावट की वजह से एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन वाली करेंसी बन गया है। बीते कुछ हफ्तों में इसमें तेज गिरावट आई है। इसकी वजह भारत का बढ़ता इंपोर्ट बिल है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ा है। इसका असर रुपये पर पड़ रहा है। क्रूड की बढ़ती कीमतों के साथ घरेलू शेयर बाजार में विदेशी फंडों की लगातार बिकवाली से भी रुपया पर दबाव बढ़ा है। फिलहाल अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत की उम्मीद नहीं दिख रही। इससे क्रूड की कीमतें ऊंचे लेवल पर बनी रह सकती हैं या और ऊपर जा सकती हैं। इससे रुपए पर दबाव और बढ़ेगा।

कर्ज जाल में फंसा पाक- अब पैसे जुटाने का तरीका बदला; चीन के पूंजी बाजार में पहली बार जारी किया पांडा बॉन्ड

इस्लामाबाद। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब कर्ज जाल में बुरी तरह फंस गया है। एक बार फिर वह पैसे जुटाने के लिए वह अपने सदाबहार मित्र चीन के पास पहुंचा है। हालांकि, इस बार उसका पैसे जुटाने का तरीका बदल गया है। दरअसल, पाकिस्तान ने पहली बार चीन के घरेलू पूंजी बाजार में पांडा बॉन्ड जारी किया है और 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। इसके साथ ही उसका चीन के पूंजी बाजार में औपचारिक रूप से प्रवेश हो गया है। पांडा बॉन्ड चीन की मुद्रा रेनमिनबी (आरएमबी) में जारी किया जाता है। इसे कोई विदेशी संस्था, संप्रभु सरकार, अंतरराष्ट्रीय संगठन या बहुराष्ट्रीय कंपनी चीन के घरेलू पूंजी बाजार में बेचती है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के सलाहकार खुर्रम शहजाद ने गुरुवार को बताया कि इस बॉन्ड पर 2.5 प्रतिशत ब्याज दर रखी गई है। इसकी अवधि तीन साल की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह पहला पांडा बॉन्ड तीन साल की निश्चित ब्याज दर वाला वित्तीय साधन है। यह चीन के घरेलू पूंजी बाजार में पाकिस्तान का पहला रिनमिनबी आधारित सरकारी बॉन्ड है। जिओ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की नजरों के बीच पाकिस्तान ने 75 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए यूरो बॉन्ड जारी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद को सऊदी अरब से

अतिरिक्त तीन अरब डॉलर की जमा राशि भी मिली और उसने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 3.4 अरब डॉलर लौटाए। इसके अलावा, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से भी 1.3 अरब डॉलर की आर्थिक मदद मिली है। यह घटनाक्रम वित्त मंत्री औरंगजेब के चीन रवाना होने के एक दिन बाद सामने आया, जहां वह पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड जारी करने के समारोह में शामिल होने गए थे।

एक बयान में खुर्रम शहजाद ने कहा कि 1.75 अरब आरएमबी (करीब 25 करोड़ डॉलर) के इस पांडा बॉन्ड को निवेशकों की जबरदस्त मांग मिली। इसके लिए 8.8 अरब आरएमबी (लगभग 1.26 अरब डॉलर) से अधिक की बोली लगी, जिससे यह पांच गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। बयान में कहा गया कि पहले चरण की मांग ही पाकिस्तान के पूरे प्रस्तावित पांडा बॉन्ड कार्यक्रम 7.2 अरब आरएमबी (करीब 1 अरब डॉलर) से ज्यादा रही। यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सुधार कार्यक्रमों पर बढ़ते वैश्विक भरोसे को दिखाता है। सलाहकार ने कहा कि यह केवल वित्त जुटाने का सौदा नहीं है, बल्कि इससे पाकिस्तान ने चीन के पूंजी बाजार में प्रवेश किया है और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि पांडा बॉन्ड की सफलता से वैश्विक निवेशकों को यह मजबूत संदेश गया है कि पाकिस्तान की आर्थिक सुधार प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। बयान में यह भी कहा गया कि इस बॉन्ड जारी करने में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एएआईबी) का सहयोग मिला है।

तहसील फरेंदा में भूमि विवादों के खात्मे की तैयारी- खाली खेतों में टीम चलाएगी विशेष अभियान

महराजगंज।

ग्रामीण क्षेत्रों में दशकों से चले आ रहे भूमि विवादों के स्थाई समाधान और सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं से मुक्त कराने के लिए उप जिलाधिकारी फरेंदा शैलेन्द्र गौतम ने कमर कस ली है।

तहसील फरेंदा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त राजस्व कर्मियों, लेखपालों और कानूनगो को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पूरे मनोयोग और निष्पक्षता से कार्य करते हुए हर गांव को भूमि विवाद मुक्त बनाने का संकल्प पूरा करें। प्रशासन का मुख्य फोकस इस समय खाली पड़े खेतों का लाभ उठाकर सीमा संबंधी (मेड़बंदी) विवादों को तत्काल निपटाने पर है।

आपसी सहमति से सुलझेंगे मेड़बंदी के विवाद, पैमाइश के नाम पर नहीं लटकेंगे मामले

एसडीएम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सीमा संबंधी जिन मामलों को आपसी बातचीत और सहमति के आधार पर सुलझाया जा सकता है, उन्हें बेवजह पैमाइश (नाप-जोख) के कानूनी वाद के नाम पर लंबे समय तक न लटकाया जाए। अक्सर देखा जाता है कि छोटे-मोटे मेड़ के विवाद कानूनी दांव-पेंच में फंसकर सालों-साल चलते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों का समय और धन दोनों बर्बाद होता है। अब लेखपालों को गांव-गांव जाकर मौके पर ही दोनों पक्षों को बैठाकर बीच का रास्ता निकालने का निर्देश दिया गया है।

ग्राम सभा और भूमि प्रबंधन समिति की ली जाएगी मदद

एसडीएम ने शासनादेशों का शत-

प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए राजस्व टीम को निर्देशित किया गया है कि वे विवादों के निपटारे में गांव के निष्पक्ष व संभ्रांत नागरिकों तथा भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों का सहयोग लें।

स्थानीय लोगों की मौजूदगी में होने वाले फैसले अधिक व्यावहारिक और स्वीकार्य होते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीणों के बीच आपसी सौहार्द भी मजबूत होगा।

खेत खाली होने का सुनहरा मौका, कानूनगो करेंगे संवेदनशील मामलों की पहचान

एसडीएम ने कहा कि वर्तमान समय में रबी की फसल कटने के बाद अधिकांश खेत पूरी तरह से खाली हैं। प्रशासन का मानना है कि यह समय सीमा संबंधी विवादों को मौके पर जाकर हल करने के लिए सबसे उपयुक्त है।

सभी क्षेत्र के कानूनगो (राजस्व निरीक्षकों) को पाबंद किया गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों का दौरा करें, पुराने या सुलगते हुए विवादों की पहचान करें और प्राथमिकता के आधार पर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

गंभीर मामलों के लिए गठित होगी संयुक्त राजस्व टीम

उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र गौतम ने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि जिन मामलों में विवाद की स्थिति गंभीर हो या शांति भंग होने की आशंका हो, वहां तत्काल प्रभाव से संयुक्त राजस्व टीम का गठन किया जाए। यह टीम मौके पर जाकर पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई करेगी। किसी भी स्तर पर पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर कानून सम्मत अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा महा-अभियान; तय होगी जवाबदेही

एसडीएम ने बैठक में भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों को भी कड़ा संदेश दिया गया है। तहसील के समस्त ग्रामों में सरकारी भूमि, चारागाह, पोखरे, खेल के मैदान और ग्राम समाज की जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर एक बड़ा अभियान चलाकर खाली कराया जाएगा।

महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वछता को लेकर राय सरकार गंभीर - आरती सिंह राव

चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राय सरकार प्रदेश में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वछता को लेकर पूरी तरह से सज़ग और गंभीर है। उन्होंने बताया कि ÷स्वछता, सम्मान और सशक्तिकरण÷ के उद्देश्य से महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत ÷मेनस्ट्रुअल हाइजीन मिशन÷ को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की बीपीएल श्रेणी की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म स्वछता के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सरल प्रक्रिया के तहत निर्धारित पोर्टल पर 20 मई, 2026 तक आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से भी योजना की जानकारी और सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना, स्वछता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी पात्र महिलाओं और किशोरियों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।

महिलाएं व बचे समाज का आधार, इन्हें सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता- मुख्यमंत्री

(संवाददाता)

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अगले 5 वर्षों की कार्ययोजना की समीक्षा की

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाएं व बचे किसी भी समाज व देश का आधार होते हैं, इनको सशक्त किए बिना राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता है। महिलाओं व बचों को सशक्त करना हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग अगले 5 साल की अपनी कार्ययोजना इसी तथ्य को ध्यान में रखकर तैयार करे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश हरियाणा विजन-2047 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की आगामी 5 वर्षीय कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का मकसद एक समावेशी और न्यायसंगत समाज का निर्माण करना है जहां महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो, वे हिंसा से मुक्त हों और जहां प्रत्येक बचे को सुरक्षित, स्वस्थ और सहायक वातावरण में पाला-पोसा जाए, साथ ही विकास और उन्नति के पूर्ण अवसर प्राप्त हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बचा अपनी आयु के अनुरूप शारीरिक व मानसिक माइलस्टोन कवर कर रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग बचों के लिए विविध गतिविधियां शुरू करवाए। हर आयु वर्ग के बचों के लिए बेबी शो तथा स्वास्थ्य प्रतियोगिता शुरू करवाई जाए जिनके विजेता बचों को पुरस्कृत भी किया जाए। समाज, परिवार व सरकार के प्रतिनिधियों को भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। इन गतिविधियों से माताओं में बचों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि बचों के जीवन के पहले 6 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिन पर उनका पूरा भविष्य निर्भर करता है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य व जागरूकता के बिना आदर्श परिवार व स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि बचों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी माताओं के हाथों ही सुरक्षित हो सकता है। इसलिए महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक करने की रणनीति को भी विभाग अपनी आगामी कार्य योजना में शामिल करे। महिलाओं को अछा माहौल देने तथा सशक्त करने के लिए हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमैन होस्टल व उनके बचों के लिए क्रेच सेंटर भी खोले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग बेटियों की जन्मदर बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में महिलाओं के बीच जन-जागरूकता की विशेष कार्ययोजना तैयार करे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात की दर को राष्ट्रीय औसत, 933 से भी अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित कर इसे प्राप्त करने की दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने महिलाओं व बचों के लिए अनीमिया जांच का लक्ष्य बढ़ाने तथा जरूरत के अनुसार सप्लीमेंट्स उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 3 साल तक के बचों व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को विशेष पोषण सामग्री प्रदान करने के संबंध में भी हिदायतें दीं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जिलावार वुमैन एम्पावर इंडेक्स बनाया जाए ताकि पता लग सके कि किस जिले में महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रभावी ढंग से जागरूक करने के लिए जरूरी है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स व सहायकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी ने बताया कि इस समय प्रदेश में 25962 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर्स व सहायक को महिलाओं व बचों से संबंधित कई प्रकार का विवरण ऑनलाइन करना होता है, इसलिए इनकी योग्यता को बढ़ाने तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी, निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी, मुख्यमंत्री के ओएसडी व स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू तथा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

भूमि विवादों के समाधान के लिए सभी जिलों में लगाई जाएं राजस्व लोक अदालतें- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। हरियाणा में जमीन संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व लोक अदालतें लगाई जाएंगी जिनके माध्यम से उपायुक्त, एसडीएम व तहसीलदार विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवादों का समयबद्ध ढंग से समाधान करवाएंगे। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित भारत-2047 के अंतर्गत तैयार किए गए 5 वर्षीय कार्यान्वयन रोडमैप और कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कही। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं एफसीआर डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राजस्व संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए विभाग द्वारा डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि विवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा सके। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भूमि विवादों के तीव्र समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व लोक अदालत लगाई जाएं जिसमें संबंधित अधिकारी दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाएं। इसके लिए सभी जिलों में पटवारियों के माध्यम से लोगों को सूचित व जागरूक किया जाए और उपायुक्त, एसडीएम तथा तहसीलदार लक्ष्य निर्धारित कर भू-विवादों का समाधान करवाएं ताकि आमजन को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में परंपरागत तरीकों से अलग हटकर नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएं ताकि आमजन को सभी सरकारी सेवाएं पारदर्शी व सरल तरीके से मिल सकें। उन्होंने कहा कि सभी नव-नियुक्त पटवारियों के लिए लैपटॉप व टेबलेट की खरीद की जाए और हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि सभी पटवारी डिजिटल माध्यम से सेवाएं दे सकें। पटवारियों को नई तकनीक व राजस्व कार्यों में पारंगत करने के लिए राय स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में सभी प्रकार के स्टाम्प की बिक्री ई-स्टाम्प के माध्यम से की जाए और इनकी बिक्री को ब्लॉक-चैन आधारित करने की दिशा में कार्य किया जाए ताकि स्टाम्प की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि उन व्यक्तियों के लिए फेसलेस रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाए जो कहीं बाहर दूसरे राज्यों या विदेश में रहते हैं और रजिस्ट्री के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में पेपरलैस रजिस्ट्रेशन कार्य की जानकारी मांगने पर अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत अब तक 4 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसी भी तहसील में 15 दिन से पुराना कोई भी रजिस्ट्रेशन आवेदन लंबित नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजस्व विभाग द्वारा अपने डाटा की स्टोरेज के लिए ह्यारट्रोन के माध्यम से प्रदेश में अपडेटिड डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए टेंडर किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शहरी संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड को प्रॉपर्टी आईडी के साथ लिंक करवाकर सुव्यवस्थित करवाने के भी निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कृषि विभाग के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण और इनकी जीयो-टैगिंग का कार्य किया जा रहा है।